श्री राज बहादुर : ऐसी शिकायतें आती हैं तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, उन पर जो कुछ भी हम लोग जांच करते हैं वह की जाती हैं और जैसे ही वह शिकायतें प्रमाणित हो जाती हैं हम उस का कोटा कम कर देते हैं, बन्द कर देते हैं और अन्य कार्यवाही करते हैं।

Agreement with Burma *Re* Assets of Indians in Burma

+

*246. **Shri Bagri:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Surendra Pal Singh:
Dr. P. N. Khan:
Dr. M. M. Das:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri Liladhar Koteki:
Shri N. R. Laskar:
Shri R. Barua:
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 24 on the 25th July, 1966 and state:

(a) whether any agreement has since been arrived at with the Burmese Government regarding the movable and immovable properties of the Indians left by them there at the time of migration; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir. The matter is still under discussion with the Burmese Government.

(b) As the discussions are of a confidential nature the disclosure of details at this stage might adversely affect their outcome.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कितना पुराना सवाल है, बहुत काफी अरसा हो गया, बर्मा से हिन्दुस्तानियों के निकास का और उनकी जायदाद का मसला तय नहीं हुआ तो किस अरसे तक यह काम हो सकेगा, कोई इसकी मियाद है जिस के आधार पर यह सोचा जा सके कि इस का कोई नतीजा निकलेगा या सिर्फ टालने वाली बात है जिससे कि कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से इसमें कोई टालने की या देर करने की कोई बात नहीं है। हम इस प्रयत्न में लगे हैं कि जल्दी से जल्दी यह मामला तय हो जाये। कई मर्तबा इसके बारे में बर्मा सरकार से बातें हुईं, यहां से लोग गये और वहां उन्होंने बातें की लेकिन अभी हम इस का कोई निर्णय नहीं कर पाये हैं इसका हमें खेद है।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय के ज्ञान में यह चीज है कि जिन हिन्दुस्तानियों को बर्मा से निकाला गया उन में ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी कि खुद की जायदाद की बात तो दरकिनार उनके जेवरों वगैरह के सिलसिले में भी उनको गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारियों की तादाद सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित न हो कर महिलाओं तक की हुई है और कुछ तो हिन्दुस्तानी बर्मा की जेलों में मर भी गए हैं और क्या यह सत्य नहीं है कि पोद्दार नाम का एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बर्मा की जेल में मर भी गया था ? क्या सरकार यह सब बात जानते हुए कि बर्मा हिन्दुस्तान का पड़ौसी और मित्र मुल्क होकर भी हिन्दुस्तान के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे तो उस का क्या कारण है ? जहां बर्मा सरकार सख्ती कर रही है यह हिन्दुस्तान सरकार बिल्कुल असमर्थ और कमजोर है जोकि अपने हिन्दुस्तानियों की हिफाजत नहीं कर सकती ?

श्री हरि विष्णु कामत : निकम्मी सरकार है।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर इस सदन में कई मर्तबा बहस हो चुकी है और आप उस से भलीभांति परिचित हैं और मेरे लिए इन सब और दोगर बातों का जल्दी से उत्तर दे देने में दिक्कत है। मैं तो यही कह सकता हूं कि कोई नई बात माननीय सदस्य ने सामने नहीं रक्खी है और सब के बारे में यहां विस्तार-पूर्वक बहस हो चुकी है।

श्री बागड़ी : जेल के अन्दर आदमी मरे हैं क्या इस का आप को पता है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी ने एक आदमी का नाम लिया पोद्दार नाम का आदमी जेल में मरा।

श्री दिनेश सिंह : मैं उनका नाम तो एकदम से नहीं बतला सकता लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहेंगे तो मैं पता लगा कर बतला दूंगा।

श्री बागड़ी : मैं ने सुना नहीं क्या जवाब मंत्री जी ने दिया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि उसका उन्हें पता नहीं बाकी पता लगा कर आप को दे देंगे।

श्री बागड़ी : आखिर इतनी भी क्या अज्ञानता ? वे महामूर्ख हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने इस शब्द को वापिस लें।

श्री बागड़ी : महामूर्ख के अपने शब्द को वापिस लेते हुए उन के लिए मैं महा अज्ञानी शब्द कहता हूं।

Shri Priya Gupta: On a point of order. Starred question No. 246 has been admitted . . .

Shri Tyagi: On a point of order.

माननीय सदस्य ने अज्ञानी शब्द को वापिस लेते हुए महा अज्ञानी शब्द कहा है।

श्री मधु लिमये : त्यागी जी, आपने . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये क्यों खड़े हो रहे हैं मैं सुन तो रहा हूं।

Shri Priya Gupta.

Shri Priya Gupta: Starred question No. 246 has been admitted after scrutiny and knowing full well that supplementary questions of this type can be asked. Therefore, how could the Minister say that this question is not admissible and cannot be answered? If what he contends is correct, why has this been accepted?

Mr. Speaker: He does not say that. This is no point of order.

Shri Priya Gupta: He said he could not reply to the question.

Mr. Speaker: Order, order. All this is unnecessary.

श्री यशपाल सिंह : बर्मा कोई करार करे या न करे क्या सरकार यह बतला सकती है कि जो हमारे भारतीय भाई उजड़ कर आये हैं उनको किस तरह से मुआवजा दिया जाय ? कितने भाई ऐसे हैं जो बस चके हैं और कितने एसे हैं जिनका कि पुन-र्वास नहीं हो सका है ? जो लोग वहां बहुत बड़ी-बड़ी जायदादें छोड़कर आए हैं उन को बर्मा सरकार अपने कब्जे में कर रही है तो उन लोगों को यहां किस तरीके से मुआविजा दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : ठाकुर साहब अब यह दूसरा सवाल आ गया। क्या मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : किस तरीके से हम यहां उनके बसाने के लिए अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं उसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर मैं पिछले सैशन में रख चुका हूं।

Shri Surendra Pal Singh: What are the main reasons for the unpopularity of Indians in Burma and why they

are being forced to leave that country?

अध्यक्ष महोदय : अब अनपापुलैरिटी के रीजंस में जाना बेसूद है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो भारतीय बर्मा से वापिस आये हैं वे दो प्रकार की सम्पत्ति छोड़कर आए हैं एक चल और दूसरी अचल सम्पत्ति तो क्या सरकार के पास बर्मा सरकार के सूत्रों से या जो वहां से लोग आये हैं उनकी जानकारी से कोई ऐसी इत्तिला मौजूद है, सरकार ने कोई ऐसी सूची बनाई है कि चल सम्पत्ति कितनी है और अचल सम्पत्ति कितनी है और बर्मा सरकार ने किन सिद्धान्तों को माना है ? वह मुआविजा देगी या नहीं देगी ? बाकी सारी वार्ता मैं नहीं जानना चाहता लेकिन जो अभी तक उस ने मान लिया है वह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री दिनेश सिंह : अभी तक कोई बात मानी नहीं गयी है पूरी बातों पर बहस हो रही है । बाकी जो माननीय सदस्य ने कहा कि दो प्रकार की सम्पत्ति है एक चल और दूसरी अचल सम्पत्ति तो यह जो बहस हो रही है यह ज्यादा अचल सम्पत्ति के ऊपर है । चल सम्पत्ति के बारे में तो इस सदन को पूरा हाल मालूम है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : चल और अचल सम्पत्ति कितनी है उस की बात नहीं बताई ।

श्री दिनेश सिंह चल और अचल सम्पत्ति मैं ने अर्ज किया कि दोनों के बारे में बातें चल रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह कितनी है ?

श्री दिनेश सिंह : अब वह कितनी है यह मेरे लिए अभी कहना मुश्किल है ।

Shri S. C. Samanta: Is it not fact that most of the movable properties were kept in the India Embassy there; if so, why cannot Government give us an approximate value of the things?

Shri Dinesh Singh: The main point, as I pointed out on the last occasion, is that the people who have left their property behind have given us a general assessment of their property. We have some assessment of it. The Burmese Government have some assessment of it. They are not all exactly the same. It is not desirable at this stage for us to say what we consider is the real value, because we have no reason to say that the value indicated by the people who have left property behind is not correct. It is a question of a final settlement.

Shri Kapur Singh: Are Government aware of any cases in which Indians, in their anxiety to save their assets, accepted Burmese nationality and as a consequence are rotting in Burmese jails ever since; if so, are Government in a position to take any steps to alleviate their predicament?

Shri Dinesh Singh: I beg of the hon. Member not to make such unfair charges about Indians abroad.

Shri Kapur Singh: I have definite cases in my view, I know the facts.

Shri Dinesh Singh: The hon. Member may allow me to finish. He has said that Indians have accepted Burmese citizenship just to save their property. That is wholly wrong. Those who have accepted Burmese citizenship are those who wanted to live in Burma.

Shri Kapur Singh: He has not answered the material portion of the question, he has gone into the motives of those who accepted Burmese nationality. The essence of the question was this. Those Indians who accepted Burmese nationality, whatever their motives, are now rotting in Burmese jails. Is the Government in a position to do anything to alleviate their predicament? He has sidetracked the question.

Shri Dinesh Singh: I would beg of the hon. Member to consider how we can intervene in the relationship between a citizen and the State there.

Would he like it if anyone from outside intervened in what we did with our citizens here?

Shri R. Barua: What is the total number of Indians coming from there, and what is the proportion of businessmen out of them?

Shri Dinesh Singh: Some of these details have already been supplied to the House. I cannot say off-hand the ratio.

Shri Priya Gupta: May I know whether the Ministry of External Affairs has information that the whole trouble of bad relations of the Burmese and Indian Governments started by virtue of the fact of the bad behaviour by Indian capitalists in Burma who wanted to exploit that country and take the money back from there, and the External Affairs representatives in Burma did not care to maintain good relations with Burma?

Mr. Speaker: Is any interest of our nation served by such a question?

Shri Priya Gupta: Does not matter, internationally it will serve.

Mr. Speaker: We ought to consider before putting questions whether the questions that we put really advance our national interest.

Next question.

Supply of Fighter Planes by U.S.A. to Iran

\+

*248. **Shri Surendra Pal Singh:**
Shri H. C. Linga Reddy:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the latest U.S. move to sell a large number of supersonic fighter interceptor planes and air-to-air missiles to Iran;

(b) if so, whether Government have sought any assurance from the U.S. Government to the effect that these planes and missiles will not find their way to Pakistan; and

(c) if so, whether that assurance has been given by the U.S. Government?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Government are aware that U.S. Government are supplying some Supersonic fighter aircraft to Iran. There are unconfirmed reports that Iran has approached the U.S. for supply of air-to-air missiles also.

(b) and (c). We have consistently drawn the U.S. Government's attention to the dangers inherent in Pakistan's determined arms build-up, including the danger that American armaments might find their way to Pakistan through third countries. It has been made clear to us that any arms supplied either on credit or as grant by the United States, cannot be transferred to any third country without their clearance. We understand that the U.S. insists on the fulfilment of this condition and we, therefore, trust that U.S. armaments supplied to third countries will not find their way to Pakistan.

Shri Surendra Pal Singh: While we welcome the assurance of the United States Government in this regard that these arms would not find their way to Pakistan. But what guarantee is there to prevent Iran from handing over these fighter planes and missiles to Pakistan through some other country?

Shri M. C. Chagla: If Iran gets any arms from the USA and hands them over to Pakistan, it would be a clear breach of the terms on which these arms were supplied by the USA. We certainly took up that matter with the U.S. Government and we have a clear and specific assurance that any arms supplied to any country cannot be transferred to any other country without the concurrence of the U.S. Government.

Shri Surendra Pal Singh: Is it not a fact that of late the USA with the co-operation and consent of the UK are making efforts to bring Pakistan and Iran together to boost up their military strength so that the two coun-